



एनडीए में शामिल 38 पार्टियों में से 9 ने नहीं लड़ा था पिछला लोकसभा चुनाव, 16 दलों के पास नहीं है एक भी सांसद

लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पिछले सप्ताह बीजेपी नीत एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया. इसमें देश के लगभग सभी राज्यों से कुल मिलाकर 38 दलों ने हिस्सा लिया. एनडीए ने ये बैचक उसी दिन बुलाई, जिस दिन विपक्षी पार्टियों के 26 दलों ने इंडिया नाम के गठबंधन की घोषणा की थी. एनडीए के सभी सहयोगी दलों की बात करें तो उनके चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं लगा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए गठबंधन के 38 दलों में



से नौ पार्टियों ने 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था. वहीं एनडीए गठबंधन के 16 दलों को पिछले आम चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि सात पार्टियों को केवल एक सीट से संतोष करना पड़ा था. पूर्वोत्तर राज्यों की कुल 11 पार्टी एनडीए, मेंबीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पिछले दो टर्म से अकेले ही लोगों का जनादेश हासिल कर केंद्र में सत्ता पर काबिज है. वहीं इस बार भी एनडीए गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी.

हाई कोर्ट में 75 फीसदी जज जनरल कैटेगरी से, सरकार ने 2018 के बाद देश के सभी हाई कोर्ट में जिन जजों की नियुक्तियां हुई हैं,

केंद्रीय विधि मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में ये जानकारी दी है. संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्हादुल मुस्लिमीनके नेता और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से जजों की नियुक्तियों को लेकर सवाल पूछा था. ओवैसी ने ट्वीट कर इस बारे में बताया. ओवैसी ने ट्वीट कर बताया कि लोकसभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में, सरकार ने खुलासा किया कि 2018 से 17 जुलाई, 2023 तक नियुक्त 604 हाई कोर्ट जज में से 458 न्यायाधीश सामान्य श्रेणी के हैं, जो 75 से अधिक हैं. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, ओवैसी ने विधि एवं न्याय मंत्रालय से पूछा कि क्या ये सच है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी हाई कोर्ट में नियुक्त 79 न्यायाधीश

उंची जातियों से थे, जो न्यायपालिका में पिछड़े और अल्पसंख्यकों के असमान प्रतिनिधित्व को दर्शाता 458 सामान्य वर्ग के हैं. हालांकि, मंत्री ने प्रतिशत नहीं बताया लेकिन ये संख्या कुल नियुक्तियों का 75

नियुक्तियों में किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाता है. हालांकि, उन्होंने बताया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यकों और महिलाओं के उपयुक्त उम्मीदवारों पर विचार करके सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने का अनुरोध कर रही है.

किंग्स वर्ग से कितने जज-कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया, 2018 के बाद सभी हाई कोर्ट में नियुक्त कुल जजों में 18 जज अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं. 9 जज अनुसूचित जनजाति, 72 अन्य पिछड़ा वर्ग और 34 अल्पसंख्यक श्रेणी से आते हैं.

पहले पति और बेटे की मौत देखी और अब बेटे के साथ यौन उत्पीड़न., मणिपुर पीड़िता की मां ने सुनाई दरिंदगी की दास्तां

प्रातीय हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में दो महिलाओं को बगैर कपड़ों के परेड कराने का वीडियो सामने आने के बाद से ही लोगों में गुस्सा भरा हुआ है. राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक सभी ने इसकी निंदा कर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है. अब इस मामले को लेकर नग्न घुमाई गई महिलाओं में से एक की मां का बयान सामने आया है. पीड़िता की मां ने, मेरे परिवार के अब कभी भी गांव लौटने की

कोई संभावना नहीं है. हमारे घर जला दिए गए हैं, हमारे खेत नष्ट

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, मणिपुर सरकार ने हिंसा को रोकने या लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं. पति और बेटे को खो चुकी हैं पीड़िता की मां इस हिंसा में अपने पति और बेटे को खो चुकी हैं. अपनी बेटी का पूरे गांव के सामने यौन उत्पीड़न होते हुए देख चुकी हैं. उनके पति और बेटे को भीड़ ने मार डाला. इसके बाद उनकी बेटी को 4 मई को सभी के सामने निर्वस्त्र किया गया

ममता बनर्जी या प्रियंका गांधी... 2024 में पीएम मोदी को कौन दे सकता है टक्कर? विपक्ष के पीएम फैंस को लेकर सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दो बड़े गठबंधन की घोषणा हो चुकी है. एक 26 विपक्षी दलों का इंडिया नाम से गठबंधन है तो दूसरा सत्तारूढ़ एनडीए है. लेकिन सबसे जहन में एक ही बात है कि आखिर मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा. इसी सवाल को लेकर पिछले सप्ताह सी-वोटर ने एक सर्वे किया है, जिस पर लोगों ने बेहद हैरान करने वाले जवाब दिए हैं.

अधर में पड़ा 545 पुलिस सब-इंस्पेक्टर का भविष्य, सिद्धारमैया सरकार ने दिए भर्तियों की न्यायिक जांच के आदेश

कर्नाटक की नव-निर्वाचित सिद्धारमैया सरकार के एक फैसले ने राज्य के 545 नव-नियुक्त पुलिस उप-निरीक्षक का भविष्य अधर में डाल दिया है. दरअसल बीजेपी के शासन काल में हुई इन भर्तियों में हुए कथित घोटाले की जांच के लिए सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया है, जिसकी जांच हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेगे. कांग्रेस ने 545 पीएसआई की भर्ती में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर तत्कालीन भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया था.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से फिर आया धमकी भरा कॉल, मलाड के व्यापारी से मांगें 20 लाख, कहा- जेल से बाहर आने के लिए चाहिए पैसे

मुंबई के मलाड इलाके में रहने वाले एक व्यापारी ने पुलिस को शिकायत दी है कि उससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग उगाही कर रहा है. व्यापारी ने बताया है कि उसको बीते दिन एक धमकी भरा कॉल रिसीव हुआ जिसमें उससे 20 लाख रुपये मांगे गए. सूत्रों ने बताया कि शिकायतकर्ता व्यापारी को 20 जुलाई के दिन शाम को एक फ़ोन नंबर से कॉल आया और कॉलर ने खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया. कॉलर ने इसके बाद व्यापारी से 20 लाख रुपये की मांग की और कहा कि उसके गैंग के लोग को जेल में है और उनको छुड़वाने के लिए उसे पैसे चाहिए. पुलिस सूत्रों ने बताया कि व्यापारी की शिकायत के आधार पर अज्ञात शख्स के खिलाफ की धारा 385 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है. लॉरेंस बिश्नोई फ़िल्हाल पंजाब की बंदिन सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है. वह 11 जुलाई से फ़रीदकोट के स्थानीय गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती किया गया था. उसे 15 जुलाई को अस्पताल से छुड़ी दे दी गई थी. डॉक्टरों ने बताया कि जब उसको यहां लाया गया था तो उसको 105 डिग्री बुखार था. जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसको डेंगू हो गया था. लॉरेंस के दखिल होने के बाद बंदिन और



फ़रीदकोट जिले की पुलिस को यहां की सुरक्षा में तैनात किया गया था. लेकिन लॉरेंस के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान एक कांड हो गया. दरअसल वहीं से बंबीह गैंग का एक गुर्गा सुरिंदर पाल बिष्ण शनिवार सुबह फ़रार हो गया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कण मच गया. गौरालव है कि बिश्नोई गैंग और बंबीह गैंग में आपस में दुश्मनी है

इस साल जून तक 87000 से ज्यादा भारतीयों ने छोड़ दी नागरिकता, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताई ये वजह

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में भारत से विदेश जाने वाले भारतीयों को लेकर बहुत अहम जानकारी दी है. एस जयशंकर ने लोकसभा में बताया कि अब तक 87,000 से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है. एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि ये संख्या जून 2023 तक दर्ज की गई है. एस जयशंकर ने बताया कि इन आंकड़ों के साथ ही 2011 के बाद से 17.50 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है. नागरिक छोड़ने वाले लोग अब उस



देश के नागरिक बन गए हैं, जहां वे जाकर बसे हैं. जयशंकर ने कहा कि इनमें से कई ने व्यक्तिगत सुविधा की वजह से विदेशी नागरिकता लेने का विकल्प चुना है. इसके अलावा पिछले दो दशकों में वैश्विक कार्यस्थल की खोज करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या महत्वपूर्ण रही है. भारत दोहरी नागरिकता की पेशकश नहीं करता है. जिसके चलते जब भारतीय विदेश जाते हैं तो जिस देश में वे गए हैं, उसके लिए पीआर सुरुक्षित करने के लिए उन्हें कभी-कभी अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने की आवश्यकता होती है. विदेश

मंत्री ने लोकसभा में कहा कि 2022 में 2,25,620 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी जबकि 2021 में उनकी संख्या 1,63,370 और 2020 में 85,256 थी. वहीं 2019 में 1,44,017, 2018 में 1,34,561, 2017 में 1,33,049, 2016 में 1,41,603 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी. इसके अलावा 2015 में 1,31,489 और 2014 में 1,29,328 ने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी. भारत छोड़कर विदेश में रहने वाले भारतीयों को कौन सा देश सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इस बारे में विदेश मंत्रालय की

आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी से अंदाजा लगाता है. विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, 2021 में कुल 78,284 लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिल गई. इसमें बताया गया कि दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया को भारतीय पसंद कर रहे हैं. 2021 के डेटा के मुताबिक 23,533 लोगों को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिली. इसके अलावा तीसरे नंबर पर कनाडा है. जहां 2021 में 21,597 लोग कनाडा के नागरिक बने. चौथे और पांचवें नंबर पर लोगों की पसंद यूके और इटली हैं.

चीन को उसी के घर में घेरना भारत! इंडियन नौवीं चीफ आज वियतनाम में नौसेना को गिफ्ट करेगे आईएनएस कृष्णा

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार शनिवार (22 जुलाई) को दक्षिण चीन सागर में एक मिलिट्री बेस पर वियतनाम नौसेना को एक ऑपरेशनल स्वदेशी जंगी जहाज कृष्णा उपहार में देंगे. माना जा रहा है कि इस कदम से भारत चीन को उसी के घर में घेरने में सक्षम होगा. अन्य उपहारों की तरह चीन का वियतनाम के साथ भी जमीन को लेकर विवाद है. वियतनाम की उत्तरी सीमा चीन से लगती है और इसके पूर्व में दक्षिण चीन सागर है. भारत और वियतनाम के संबंध सौहार्दपूर्ण हैं क्योंकि 1979 के चीन-वियतनाम युद्ध में भारत ने वियतनाम की मदद की थी, जिसके चलते चीन को पटखनी का सामना करना पड़ा था. भारत की रणनीति चीन की तरह कभी विस्तारवाद की नहीं रही है लेकिन बेकाबू होते डूंगन को घेरने में वियतनाम को उपहार में दिया जाने वाला आईएनएस कृष्णा काम आ सकता है, एसी उम्मीद की जा रही है. बता दें कि स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल से लैस कावेट (छोटा जंगी जहाज) आईएनएस कृष्णा 8 जुलाई को केम रूढ़ अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा था और वियतनामी पीपुल्स नौवीं ने इसका स्वागत किया था. भारत से वियतनाम तक की आखिरी यात्रा में इस जंगी जहाज में तिरंगा शान से लहरा रहा था.

